वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण 2018-19

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

वर्ष 2017-18 में बृहत-आर्थिक संकल्पनाएं सुदृढ़ रहीं। तथापि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2016-17 की तुलना में 2017-18 में कमतर रही। निर्यात वृद्धि में सुधार हुआ, समेकन आयोजनाओं के साथ राजकोषीय रूझान का ताल-मेल बना रहा और मुद्रास्फीति सीमाओं के भीतर रही। इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व भर के देशों के विश्वास में वृद्धि हुई तथा व्यवसाय करना आसान बनाने की रैंकिंग में सुधार आया।

वर्ष में विभिन्न आर्थिक सुधार किए गए, जिनमें माल और सेवा कर को लागू करना, बैंकों के पुनः पूँजीकरण की घोषणा, वहनीय आवास को अवसंरचना का दर्जा देकर अवसंरचना विकास को आगे बढ़ाना, राजमार्ग निर्माण हेतु निधियों का अधिक आबंटन और तटीय संपर्कता पर अधिकाधिक ध्यान केन्द्रित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, अन्य पहलों में ₹50 करोड़ तक वार्षिक कारोबार करने वाली कम्पनियों के लिए कम आयकर; मैट क्रेडिट को वर्तमान में 10 वर्ष की बजाय 15 वर्ष की अवधि तक आगे बढ़ाने के लिए अनुमत करना; व्यवसाय करना आसान बनाने में सुधार के लिए और अधिक उपाय करना तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था को विशेष बढ़ावा देना शामिल है।

किए गए अन्य क्षेत्रक वार उपायों में निर्माण क्षेत्र को फिर से गति प्रदान करने और वस्त्र एवं परिधान उद्योग में निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं। इनके अलावा, सरकार द्वारा विनिर्माण को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन, व्यवसाय करना आसान बनाने में सुधार तथा मेक-इन-इण्डिया, स्किल इण्डिया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी स्कीमों एवं वित्तीय समावेशन हेतु पिछले वर्ष किए गए उपायों को 2017-18 में भी जारी रखा गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली महत्वपूर्ण बृहत्-आर्थिक चुनौती निवेश और बचत की दरों में गिरती प्रवृत्ति से संबंधित हैं, जैसाकि अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों से देखा जा सकता है। तथापि, माल एवं सेवा कर को लागू करने, वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई आशा, अपेक्षाकृत स्थिर मूल्य और विदेशी क्षेत्र के संकेतकों में सुधार की पृष्ठभूमि में मध्यावधिक बृहत् संभावनाएं उज्ज्वल हैं।

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सतत् (2011-12) बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के संदर्भ में 2017-18 में अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.5 प्रतिशत होने की संभावना है। सतत् (2011-12) आधार मूल्यों पर सकल मूल्यवर्धन 2017-18 में 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़ सकता है जबकि 2016-17 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई थी। 2017-18 में कृषि, उद्योग और सेवा में क्रमशः 2.1 प्रतिशत, 4.4 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है; जबकि 2016-17 में इनमें क्रमशः 4.9 प्रतिशत, 5.6 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2017-18 में मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र में कम वृद्धि होने के कारण उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर में गिरावट आई। यह सेवा क्षेत्र ही था जिसका 2017-18 में 6.1 प्रतिशत की समग्र जीवीए वृद्धि दर में आधा से अधिक का योगदान था। मांग पक्ष से अंतिम उपभोग व्यय स.घ.उ. वृद्धि का मुख्य कारण रहा। सतत् मूल्य पर नियत निवेश की वृद्धि 2016-17 में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 4.5 प्रतिशत हो गई। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, 2017-18 में वास्तविक अर्थों में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 4.5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है; जैसाकि 2016-17 में हुआ था, जबकि निर्यातों में 2016-17 में 2.3 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 10.0 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है।

कृषि

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा जारी चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में खाद्यानों का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया गया, 2016-17 में इसके 275.7 मिलियन टन होने का अनुमान है जो 2013-14 में हासिल किए गए पिछले रिकॉर्ड उत्पादन की तुलना में 10.7 मिलियन टन अधिक है। 2016-17 के दौरान चावल का उत्पादन 110.2 मिलियन टन होने का अनुमान है, यह भी एक नया रिकॉर्ड है। इसी तरह, गेहूँ का उत्पादन 98.4 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2013-14 के दौरान हासिल किए गए पिछले रिकॉर्ड उत्पादन की तुलना में 2.6 प्रतिशत अधिक है। दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि दालों के उत्पादन में हुई, जिसका 2016-17 के दौरान 23.0 मिलियन होने का अनुमान है, जो 2013-14 के दौरान हासिल किए गए पिछले रिकॉर्ड उत्पादन की तुलना में 3.7 मिलियन अधिक है। 2016-17 में तिलहनों और कपास के उत्पादन में क्रमशः 27 प्रतिशत और 10.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

22 सितम्बर, 2017 को जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, खरीफ मौसम 2017-18 के दौरान खाद्यानों का उत्पादन 2016-17 के दौरान 138.5 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 134.7 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2017-18 के खरीफ मौसम के दौरान चावल का कुल उत्पादन 2016-17 में 96.4 मिलियन टन की तुलना में 96.4 मिलियन टन होने का अनुमान है। खरीफ मौसम 2017-18 के दौरान दालों का उत्पादन 8.7 मिलियन टन, गन्ना 337.7 मिलियन टन, तिलहन 20.7 मिलियन टन और कपास का उत्पादन प्रत्येक 170 किग्रा. की 32.3 मिलियन गांठ होने का अनुमान है।

पिछले दशक में, भारत में कृषि ऋण वार्षिक 17 प्रतिशत से अधिक की दर से लगातार बढ़ता आ रहा है। 2017-18 के दौरान बैंकों ने 5.88 लाख करोड़ रुपए (30 सितम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार अनंतिम) संवितिरत किया है जबकि 2017-18 के लिए ₹10 लाख करोड़ का वार्षिक कृषि ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

मूल्य

2016-17 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) मुद्रास्फिति (आधार 2012 = 100) 2015-16 में 4.9 प्रतिशत से गिरकर 4.5 प्रतिशत पर आ गई। अप्रैल-दिसम्बर, 2017 में इसका औसत 3.3 प्रतिशत था और दिसम्बर, 2017 में 5.2 प्रतिशत था। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फिति 2015-16 के 4.9 प्रतिशत से गिरकर 2016-17 में 4.2 प्रतिशत पर आ गई। अप्रैल-दिसम्बर, 2017 में इसका औसत 1.2 प्रतिशत था और दिसम्बर, 2017 में 5.0 प्रतिशत था।

2016-17 में थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मापी गई मुद्रास्फिति 2015-16 के (-) 3.7 प्रतिशत से बढ़कर 1.7 प्रतिशत हो गई। अप्रैल-दिसम्बर, 2017 में इसका औसत 2.9 प्रतिशत था और दिसम्बर, 2017 में 3.6 प्रतिशत था।

सरकार द्वारा कड़ा खाद्य प्रबंधन तथा मूल्य निगरानी नीति अपनाए जाने के कारण मुद्रास्फीति, विशेषकर, खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित स्तर पर बनाए रखने में सहायता मिली। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और मूल्य स्थिरता की बहाली के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए। किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैः (i) मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) नामक एक स्कीम का क्रियान्वयन दालों, प्याज आदि जैसी कृषि वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है; (ii) घरेलू अधिप्राप्ति तथा आयात दोनों के जरिए पीएसएफ स्कीम के अंतर्गत 20 लाख टन तक दालों का एक परिवर्तनशील सुरक्षित भंडार रखा गया है; (iii) अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की गई ताकि उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके; (iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्याज पर भंडारण सीमा लागू करने की सलाह दी गई। राज्यों को अपनी प्याज की आवश्यकता सूचित करने के लिए कहा गया ताकि उपलब्धता बढ़ाने और प्रचलित उच्च मूल्यों को कम करने के लिए अपेक्षित मात्रा में निर्यात किया जा सके; (v) देश में उपलब्धता बढ़ाने और मूल्य वृद्धि कम करने के लिए सरकार ने चीनी के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाया; और (vi) खाद्य तेलों का निर्यात केवल ब्रांडेड उपभोक्ता पैकों में 5 किलोग्राम तक 900 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन न्यूनतम निर्यात मूल्य के साथ अनुमत किया गया था। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, ताड़ तेल, सरसों तेल, सूर्यमुखी तेल को छोड़कर अन्य खाद्य तेलों पर से यह प्रतिबंध हटा दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके 5 अगस्त, 2016 से लेकर 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए +/-2 प्रतिशत के सह्यता स्तर के साथ 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उद्योग और सेवाएं

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन, जिसमें खनन, विनिर्माण और बिजली शामिल है, से यह ज्ञात होता है कि अप्रैल-नवम्बर, 2017 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। क्षेत्रक वार वर्गीकरण के अनुसार, अप्रैल-नवम्बर, 2017 के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 3.0 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उपयोग आधारित श्रेणियों में प्राथमिक वस्तुओं, पूँजी वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं, अवसंरचना/ निर्माण संबंधी वस्तुओं, उपभोक्ता गैर-टिवाऊ वस्तुओं में अप्रैल-नवम्बर, 2017 के दौरान धनात्मक वृद्धि हासिल की गई।

आठ प्रमुख अवसंरचना सहायक उद्योगों अर्थात् कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली जिनका आईआईपी में लगभग कुल 40 प्रतिशत भारांश है, में अप्रैल-नवम्बर, 2017 के दौरान 3.9 प्रतिशत की संचयी वृद्धि दर्ज की गई जबकि अप्रैल-नवम्बर, 2016 के दौरान 5.3 प्रतिशत दर्ज की गई थी। कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, सीमेंट और बिजली का उत्पादन अप्रैल-नवम्बर, 2017 के दौरान बढ़ा। इस्पात के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई जबकि इस अवधि के दौरान कच्चे तेल और उर्वरकों के उत्पादन में मामूली गिरावट आई।

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

2017-18 के दौरान मौद्रिक नीति का संचालन संशोधित सांविधिक ढांचे के अंतर्गत किया गया, जो 5 अगस्त, 2016 से लागू हुआ। 2017-18 में, दिसम्बर, 2017 तक मौद्रिक नीति समिति की पांच बैंठकें आयोजित की गई थीं। अगस्त, 2017 में 2017-18 के लिए जारी किए गए तीसरे द्विमासिक मौद्रिक नीतिगत विवरण में मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक घटाकर 6.0 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। इसने अक्तूबर और हाल में दिसम्बर में आयोजित बैठक दोनों में इन दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया। तदनुसार, नकदी समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो दर 5.75 प्रतिशत है तथा सीमांत स्थली सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.25 प्रतिशत है।

पुनर्मुद्रीकरण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 से स्थापित हुए अनुकूल आधार प्रभाव के कारण परिचालन में स्थित मुद्रा (सीआईसी) और आरक्षित धनराशि (एम0) दोनों में ही वर्षानुवर्ष वृद्धि दर में तेजी से सकारात्मक और पिछले वर्ष में उनमें हुई वृद्धि दरों की तुलना में उच्चतर वृद्धि दरों का रूझान देखने को मिला। दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार, आरक्षित धनराशि में दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के मुकाबले 54.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जिसका मुख्य कारण परिचालन में स्थित मुद्रा में बढ़ोत्तरी था जो विमुद्रीकरण से पूर्व स्तर का 94.4 प्रतिशत था।

विमुद्रीकरण के पश्चात स्थूल मुद्रा (एम 3) की वृद्धि दर में वर्षानुवर्ष सुस्ती आई थी, लेकिन आरक्षित धनराशि में कमी के विपरीत यह सकारात्मक रही, इसका कारण यह था कि समग्र जमाराशियों में उछाल आने से जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में कमी की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति हो गई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान विशेष रूप से सितम्बर, 2017 के अंत से स्थूल मुद्रा की स्थिति में वर्षानुवर्ष तेजी आई। नवम्बर, 2016 में विमुद्रीकरण के पश्चात, रिजर्व बैंक ने परम्परागत और अपरम्परागत

दोनों साधनों के मिश्रित उपयोग द्वारा अपने नकदी आमेलन संबंधी कार्यों में सुधार किया। नकदी की परिस्थितियां आधिक्य मोड में बनी रही तथा उत्तरोत्तर मुद्रीकरण के साथ इसकी उपलब्धता की स्थिति क्रमिक रूप से सामान्य होने लगी थी। हालिया महीनों में भारित औसत मांग दर नीतिगत स्वीकार्य घट-बढ़ सीमा के बीच खिसक गई थी।

बैंकिंग क्षेत्र

बैंकिंग क्षेत्र, खासकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निष्पादन में चालू वित्त वर्ष के दौरान नरमी बनी रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के सकल अनर्जक अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात मार्च, 2017 के 9.6 प्रतिशत से बढ़कर सितम्बर, 2017 में 10.2 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी और जोखिम भारित आस्ति का अनुपात मार्च और सितम्बर, 2017 के बीच 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गया।

खाद्य-भिन्न ऋण (एनएफसी) में नवम्बर, 2016 के 4.8 प्रतिशत की तुलना में नवम्बर, 2017 में वर्षानुवर्ष 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेवाओं और व्यक्तिगत उधार श्रेणी बैंक ऋण की उधारी का समग्र एनएफसी वृद्धि दर में एक बड़ा योगदान बना रहा। अक्तूबर, 2016 से अक्तूबर, 2017 तक निरंतर नकारात्मक रहने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि में अंततः सुधार हुआ। तथापि, जून, 2015 से मध्यम स्तर के उद्योगों में ऋण वृद्धि नकारात्मक रही है।

विदेशी क्षेत्र

वर्ष 2016-17 में भारत के वाणिज्यिक निर्यात का मूल्य (सीमा शुल्क आधार पर) 5.2 प्रतिशत बढ़कर 275.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। अप्रैल-दिसम्बर, 2017 में निर्यात विगत वर्ष की इसी अवधि में 12.1 प्रतिशत बढ़कर 199.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 223.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

वर्ष 2016-17 में आयात में भी 0.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अप्रैल-दिसम्बर, 2017 की अवधि के दौरान 338.4 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का आयात किया गया जिससे विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान किए गए 277.9 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात होती है। पेट्रोलियम, तेल और स्नेहकों (पीओएल) का आयात अप्रैल-दिसम्बर, 2017 के दौरान विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 61.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 24.2 प्रतिशत बढ़कर 76.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। इसका मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि रही। अप्रैल-दिसम्बर, 2017 के दौरान पेट्रोलियम, तेल स्नेहक- भिन्न आयात का मूल्य पिछले वर्ष की इसी अवधि के 216.6 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 21.1 प्रतिशत बढ़कर 262.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

व्यापार घाटा अप्रैल-दिसम्बर, 2017 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के 78.4 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 114.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

वर्ष 2017-18 के प्रथम छः माह के उपलब्ध भुगतान शेष के आंकड़ों के आधार पर भुगतान शेष पर आधारित व्यापार घाटा अप्रैल-सितम्बर, 2016 के 49.4 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल-सितम्बर, 2017 में 74.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। निवल अदृश्य अधिशेष निवल सेवाओं और निवल निजी अंतरणों में देखी गई वृद्धि के चलते 2016-17 के पूर्वार्ध के 45.7 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2017-18 के पूर्वार्ध में 52.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। वर्ष 2017-18 के पूर्वार्ध के दौरान वर्षानुवर्ष आधार पर निवल सेवा प्राप्तियां 14.6 प्रतिशत बढ़ी हैं।

वर्ष 2017-18 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 2016-17 (अप्रैल-सितम्बर) के 20.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 19.6 बिलियन अमरीकी डालर हुए थे जबकि निवल पोर्टफोलियो 2017-18 (अप्रैल-सितम्बर) में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के 8.2 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 14.5 बिलियन अमरीकी डालर हुए थे।

भारत का चालू खाता घाटा 2016-17 के पूर्वार्ध के 3.8 बिलियन अमरीकी डालर (सघउ का 0.4 प्रतिशत) से बढ़कर 2017-18 के पूर्वार्ध में 22.2 बिलियन अमरीकी डालर (सघउ का 1.8 प्रतिशत) हो गया। भुगतान शेष के आधार पर 2017-18 (अप्रैल-सितम्बर) में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 20.9 बिलियन अमरीकी डालर का निवल संग्रहण हुआ था जबकि मूल्यांकन परिवर्तनों सहित यह 30.3 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ा था। इसके परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा भंडार के स्टाक में वृद्धि हुई थी जो सिताबर अंत 2017 में 400.2 बिलियन अमरीकी डालर पर डटा हुआ था। विदेशी मुद्रा भंडार का स्टाक 29 दिसम्बर, 2017 को 409.4 बिलियन अमरीकी डालर था। हालांकि, व्यापार घाटा 2016-17 के पूर्वार्ध की तुलना में 2017-18 के पूर्वार्ध में बढ़ा था परन्तु अदृश्य प्राप्ति शेष और विदेशी निवेश की प्रमुखता से निवल पूंजी प्रवाहों में सुधार और बैंकिंग पूंजी चालू खाता घाटे के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त से अधिक थी जिसके कारण 2017-18 के पूर्वार्ध में विदेशी मुद्रा के आरक्षित भंडार में वृद्धि हुई।

वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) में रुपये की औसत मासिक विनिमय दर (भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर) अप्रैल, 2017 में ₹64.51 प्रति अमरीकी डालर थी और यह दिसम्बर, 2017 में ₹64.24 प्रति अमरीकी डालर थी। रुपये में 2.5 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि हुई जो मार्च, 2017 में ₹65.88 प्रति अमरीकी डालर से दिसम्बर, 2017 में ₹64.24 प्रति अमरीकी डालर हो गया।

केंद्र सरकार के वित्त साधन

राजकोषीय समेकन के संबंध में प्रतिबद्धता से सरकार को 2016-17 में राजकोषीय घाटे के संबंध में बजट विहित सघउ के 3.5 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिली। वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा क्रमशः 5,46,532 करोड़ रुपये (सघउ का 3.2 प्रतिशत) और ₹3,21,163 करोड़ (सघउ का 1.9 प्रतिशत) होने का अनुमान है।

वर्ष 2017-18 के संबंध में लगाए गए बजटीय अनुमान में कर और सघउ अनुपात 11.3 प्रतिशत तथा कुल व्यय और सघउ अनुपात 12.7 प्रतिशत होने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में सकल कर राजस्व में परिकल्पित वृद्धि 12.2 प्रतिशत ज्ञात हुई। बजट अनुमान 2017-18 में कुल व्यय में 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 6.6 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी किए गए अप्रैल-नवम्बर, 2017 के संबंध में केन्द्र सरकार के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार सकल कर राजस्व में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह आंकड़ा 2017-18 के बजट अनुमान का 56.9 प्रतिशत था। कर-भिन्न राजस्व में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 39.7 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। इसके विपरीत, नवम्बर, 2017 के अंत में ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों में 89.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2017-18 के बजट अनुमान के 73.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया।

अप्रैल-नवम्बर, 2017 के दौरान अप्रैल-नवम्बर, 2016 की तुलना में प्रमुख सब्सिडियों में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल-नवम्बर, 2017 के दौरान खाद्य सब्सिडी में ₹12,196 करोड़ की तथा पेट्रोलियम सब्सिडी में ₹2518 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि 2016-17 की इसी अवधि में उर्वरक सब्सिडी में ₹6,437 करोड़ की कमी आई।

वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवम्बर) में राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा क्रमशः बजट अनुमान का 112 प्रतिशत और 152.2 प्रतिशत दर्ज किया गया जो पांच वर्षों के औसत आंकड़े अर्थात बजट अनुमान के क्रमशः 89.2 प्रतिशत और 97.8 प्रतिशत की तुलना में उच्च स्तर पर था। वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा सघउ का क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 2.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

संभावनाएं

वर्ष 2017-18 में किए गए सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप विकास की गति के सुदृढ़ और मजबूत होने की आशा है। वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में संभावनाओं का अनुमान उभरते हुए वैश्विक तथा घरेलू घटनाक्रमों के आलोक में लगाए जाने की आवश्यकता है। वैश्विक आर्थिक विकास की गति में मामूली सुधार होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। इससे भारत से निर्यात में और अधिक वृद्धि होने की आशा है जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में पहले से ही वृद्धि दिखाई देने लगी है। दूसरी ओर, तेल तथा अन्य प्रमुख वस्तुओं के वैश्विक मूल्यों में वृद्धि होने से आयात पर होने वाले व्यय में वृद्धि हो सकती है। अर्थव्यवस्था में निवेश क्रियाकलापों में फिर से सुधार होने के संकेत तथा स्थायी निवेश में वृद्धि की दर बढ़ने से आगामी वर्ष के दौरान निवेश की गति बने रहने की आशा है। बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था में और अधिक मजबूती आने के संबंध में लगाए गए अनुमानों को देखते हुए अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्त वर्ष 2018-19 में 11.5 प्रतिशत रहने की आशा है।

अनुबंध-1

वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण
(आर्थिक निष्पादन : एक दृष्टि में)

क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य अप्रैल-दिसम्बर		प्रतिशत परिवर्तन अप्रैल-दिसम्बर	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
संपदा क्षेत्र					
1.	बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ हजार करोड़)@				
	(क) वर्तमान मूल्यों पर	15184	16628	11.0	9.5
	(ख) वर्ष 2011-2012 के मूल्यों पर	12190	12985	7.1	6.5
2.	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (2011-12=100)*	117.8	121.6	5.5	3.2
3.	थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	111.2	114.4	0.7	2.9
4.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांकः नई श्रृंखला (2012=100)	130.2	134.5	4.8	3.3
5.	मुद्रा आपूर्ति (एम3) (₹ हजार करोड़)	12045.0	13272.4	3.7	3.8
6.	वर्तमान मूल्यों पर आयात**				
	(क) ₹ करोड़	1865152	2182290	-3.2	17.0
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	277899	338370	-6.6	21.8
7.	वर्तमान मूल्यों पर निर्यात**				
	(क) ₹ करोड़	1338342	1441420	4.7	7.7
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	199467	223513	1.1	12.1
8.	व्यापार घाटा (मिलियन अमरीकी डालर)**	-78432	-114857	-21.6	46.4
9.	विदेशी मुद्रा भंडार (29 दिसंबर 2017 तक)				
	(क) ₹ करोड़	2437640	2617690	5.4	7.4
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	358898	409367	2.4	14.1
10.	चालू खाता शेष (मिलियन अमरीकी डालर)##	-3868	-22244		
	सरकार के वित्त साधन (₹ करोड़)#				
1.	राजस्व प्राप्तियां	796123	804861	24.8	1.1
	कर (केन्द्र को निवल)	621172	699392	33.6	12.6
	कर-भिन्न राजस्व	174951	105469	1.0	-39.7
2.	पूंजी प्राप्तियां, जिसमें	490558	673954	-2.7	37.4
	ऋणों की वसूली	9033	9471	14.7	4.8
	अन्य प्राप्तियां	23529	52378	83.1	122.6
	उधार और अन्य देनदारियां	457996	612105	-5.3	33.6
3.	कुल प्राप्तियां (1+2)	1286681	1478815	12.6	14.9
4.	कुल व्यय	1286681	1478815	12.6	14.9
	(क) राजस्व व्यय	1144334	1294700	16.4	13.1
	जिसमें				
	ब्याज भुगतान	266678	309799	5.6	16.2
	(ख) पूंजी व्यय	142347	184115	-10.4	29.3
5.	राजस्व घाटा	348211	489839	0.8	40.7
6.	राजकोषीय घाटा	457996	612105	-5.3	33.6
7.	प्राथमिक घाटा	191318	302306	-17.2	58.0

@ सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े अप्रैल से मार्च तक के हैं और वर्ष 2016-17 के आंकड़े अनंतिम अनुमान हैं और वर्ष 2017-18 के आंकड़े प्रथम अग्रिम अनुमान हैं।

** अप्रैल-नवंबर*

*** सीमाशुल्क आधार पर (अप्रैल-दिसंबर)। # अप्रैल-नवंबर और महालेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संसूचित आंकड़े।*

अप्रैल - सितंबर